प्रतिरक्षा भारती
Pratiraksha Bharti

भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ का मुख पत्र

जनवरी २०२५ • वर्ष-विंशति (२१) • अंक ०१ • मूल्य : १० • वार्षिक मूल्य : १२०₹

5 सूत्रीय मांगों हेतु 15 दिनों के आन्दोलन का प्रारुप तैयार करते
श्रीमान् साधू सिंह, महा सचिव, राष्ट्रीय कर्मचारी सरकारी परिसंघ एवं भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ के पदाधिकारी गण

5 सूत्रीय मांगों को लेकर आन्दोलन करते भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ के कार्यकर्ता

देश भर के रक्षा संस्थानों के प्रतिनिधि क्षेत्रीय सांसद के माध्यम से मा० प्रधानमंत्री महोदय को ज्ञापन प्रेषित किया।

माननीय रक्षाताई खडसे, सांसद (रावेर, महाराष्ट्र) को ज्ञापन देते महासंघ के कार्यकर्ता

मा० श्री नीलेश जी लंके, सांसद (अहमद नगरक्षेत्र) को ज्ञापन देते हुए VRDE सिविलियन इम्प्लाईज यूनियन के कार्यकर्ता

मा० एस.पी.सिंह बघेल, सांसद (आगरा क्षेत्र) को ज्ञापन देते हुए ओईएफ कर्मचारी संघ के कार्यकर्ता

मा० कविता पाटीदार, राज्य सभा सांसद को ज्ञापन देते हुए एमईएस कामगार यूनियन के कार्यकर्ता

सम्पादक की कलम से

– श्री साधू सिंह

प्रिय मित्रों।

आप सभी को बहुत बहुत बधाई। आप सभी ने फिर से एक विजय प्राप्त की। दिनांक 15 जनवरी 2025 से 30 जनवरी 2025 तक आंदोलन प्रारम्भ किया। आंदोलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय परिसंघ ने माननीय प्रधानमंत्री और माननीय वित्तमंत्री से पत्र के माध्यम से अपनी मांग पहुँचाई। बजट पूर्व वार्ता में भारतीय मजदूर संघ ने वित्तमंत्री महोदय के समक्ष तमाम विषयों के साथ 8वें वेतन आयोग की मांग और NPS को समाप्त कर OPS लागू करने की बात उठाई। पिछले एक वर्ष से लगातार आंदोलन, पत्राचार, प्रस्ताव के माध्यम से अपनी मांग रखी। 8वें वेतन आयोग का गठन आंदोलन प्रारम्भ होने के दूसरे ही दिन भारत सरकार ने घोषणा की, अनुकम्पा नियुक्ति का ड्राफ्ट पालिसी जारी हो चुकी है।आधी अधूरी NPS से OPS तो नहीं मिला लेकिन UPS का नोटिफिकेशन भी जारी हुआ। जिसका विरोध OPS मिलने तक जारी रहेगा। कारपोरेशन समाप्त करने सेवानिवर्त तक सरकारी कर्मचारी बनाये रखने के लिये प्रयास लगातार जारी है। रिक्त स्थानों को भरने के लिये प्रयास जारी है। आप सभी को ज्ञात है कि भारतीय मजदूर संघ, सरकारी राष्ट्रीय परिसंघ, भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ के आंदोलनों से बहुत कुछ प्राप्त होता है चाहे वेतन आयोगों का गठन हो NPS में बिभिन्न सुधार हों या बोनस की सीलिंग सीमा बढ़ाने की बात हो सभी में सफलता मिलती है। फिर भी हमारे संगठनों, यूनियंस को लाभ क्यों नहीं मिलता इस पर आप सभी को मंथन करने की आवश्यकता है आप अनेकों आंदोलन करते सफलता भी मिलती फिर भी हम पीछे। कारण क्या है? सोचिए और सुधार की आवश्यकता है। आगे हमें आंदोलन जारी रखने होंगे हमें बजट का इंतजार है कि क्या कुछ मिलता है या नहीं और इसके बाद संघर्षो का सिलसिला शुरू होगा।

मित्रों सरकारी कर्मचारियों को वेतन आयोग का इंतजार रहता है और जब अपेक्षा पूरी नहीं होती तो घोर निराशा होती है। हमें वेतन आयोग के समक्ष कर्मचारियों के वेतनमानों, भत्ते एवम अन्य सेवा शर्तों के सम्बंध में बहुत सोच समझकर रखनी होगी। वेतन आयोग और सरकार तक अपनी मांगों को ठीक से रखने के लिये कटिबद्ध है वेतनमानों के साथ भत्ते भी 1जनवरी 2026 से प्राप्त हों इसके लिये प्रयास करना है।

मित्रों 24 जनवरी 2025 को एक भीषण दुर्घटना ऑर्डनन्स फैक्ट्री भण्डारा में हुई हमारे आठ कर्मचारियों की जान गई। हम सभी अत्यंत दुखी हैं एक ट्रेड अप्रेंटिस बच्चा भी शहीद हुआ इस घटना को लेकर अपनी यूनियन ने बहुत जबर्दस्त प्रयास किया पीड़ित परिवारों को उचित मुआवजा परिवार के सदस्य को नौकरी के लिये संघर्ष किया सफलता भी मिली अपने महासंघ ने भी घटना को लेकर रक्षा मंत्रालय को पत्र लिखा है। मित्रों इसके पूर्व OF खमरिया में भी दुर्घटना हुई और कर्मचारियों को अपनी जान गवानी पड़ी। कहीं न कहीं कुछ तो गड़बड़ है ट्रेड अप्रेंटिसस को सेंसटिव एरिया में कार्य पर लगाना यह पूरी तरह गलत है, सेफ्टी उपकरणों और सेफ्टी नॉर्म्स का पालन न कराना यह गड़बड़ियों के कारण कर्मचारियों को अपने प्राणों की आहुति देना। इन सब पर रोक लगनी चाहिए। किसी को कहीं भी पोस्ट करना यह सब गड़बड़ियों से कर्मचारियों की जन हानि हो रही है। यह स्टेटमेंट देना कि एक्सीडेंट तो होते ही रहते है अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ना है। MIL को गम्भीरता से विचार करना होगा। इस दुर्घटना की निष्पक्ष जांच हो घटना के कारणों को जानना और भविष्य में पुनरावृति को रोकना होगा। जो दोषी है उनके खिलाफ कठोर कार्यवाही की आवश्यकता है कारपोरेशन के बाद काम का दबाव तो घटना का कारण तो नहीं है यह सब जानना बहुत ही आवश्यक है। मृत आत्माओं को प्रभु शांति प्रदान करें परिवार को इस दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। इस दुःख की घड़ी में हमारी यूनियन और महासंघ पीड़ित परिवार के साथ खड़ा है।

❐

GENERAL SECRETARY MESSAGE TO KARYKARTA

A New Journey Towards Excellence

It is with immense gratitude and humility that I express my heartfelt thanks to all the respected Karyakartas of Bharatiya Pratirakshya Mazdoor Sangha for entrusting me with the responsibility of serving as the General Secretary.

The 20th Triennial Conference was held at Ordnance Factory Ambhajhari Nagpur from 27-29th December 2025, and will remain a momentous occasion in my life. Your unwavering faith and support inspire me to work with renewed energy and dedication to uphold the principle and objectives of our esteemed organisation.

As we move forward and inspiration from the teaching of our revered founder, late Dattopant Thengadi ji . His visionary leadership and unwavering commitment to the cause of workers have laid the foundation of Bharatiya Mazdoor Sangha. He taught us the value of unity, discipline and selfless service to the nation. It is our duty to to follow the path he has shown us and to imbibe his principles in our daily actions.

The road ahead is not without challanges. The rapid changing industrial landscape, globalization and technological advancements present new obstacles for the working class. However with hard work, dedication and clear vision we can overcome these hurdles and ensure that BPMS emerges as the leading federation in the coming days. Our collective efforts will strengthen not only our organisation but also the industries and, ultimately, the nation.

i appeal to each one of you to work unitedly with full confidence, dedication and devotion.

Let us strive to strengthen our Federation in every corner of the country, ensuring that our presence is felt and our voice is heard. Together, We can address the challanges of the future and create a brighter tomorrow for our nation, industries and the workers. Let us stay committed to our goals and continue our journey with the spirit of service and unity.

With gratitude and determination let us pledge to upload the values of Bharatiya Pratirakshya Mazdoor Sangha and take it to greater heights.

Jai Hind - Jai Bharat

- Ravindra Mishra

OUR STRUGGLE

Success Is Not Comes In A Day

सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय परिसंघ

Govt. Employees National Confederation

(AFFILIATED TO B.M.S.)

सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय परिसंघ

Govt. Employees National Confederation

(AFFILIATED TO B.M.S.)

CENTRAL OFFICE : RAM NARESH BHAWAN, TILAK GALI, PAHAR GANJ, NEW DELHI - 110055

SUB OFFICE : 2-A, NAVEEN MARKET KANPUR-208 001

No. GENC/FM/ 8th CPC & UPS /193(B7/L)

Date: 13.12/2024

To,

Mrs. Nirmala Sitharaman Ji,
Hon'ble Finance Minister,
North Block,
New Delhi-110001.

Sub: Constitute 8th CPC to revise the pay, allowances and service conditions of Central Government employees and restore OPS in place of NPS/UPS.

Respected Madam,

The "Government Employees National Confederation" is a Confederation affiliated to the "Bhartiya Mazdoor Sangh". This Confederation coordinates the organizations representing central and state employees. The meeting of the Working Committee of the Confederation was held virtually on 11 January 2024. The Working Committee has unanimously decided that the Confederation should immediately demand the formation of the Eighth Pay Commission, making the sentiments of the central and state employees known.

Madam, as is known, a Pay Commission has been constituted every 10 years to revise the salaries, allowances and service conditions of central employees. The 7th CPC was constituted in 2013, which presented its recommendations in 2015. The government studied the recommendations and implemented the recommendations of the 7th CPC in July 2016 from 1 January 2016. There has been a delay in the formation of the Eighth Pay Commission. The Pay Commission takes about 3 years to prepare its report. Madam, the Confederation would like to make you aware of the sentiments of the employees and request you to announce the formation of the Eighth Pay Commission in the general budget of the year 2025-26.

Madam, it has been a long standing demand of the employees that the NPS applicable to employees who joined government service after 2004 should be abolished and pension should be given as per CCS Pension Rules 1972. Employees have been opposing NPS from the very beginning and have been agitating for a long time. Bhartiya Mazdoor Sangh and affiliated unions have also been continuously protesting. Since 2004, memorandums have been given to the government through demonstrations and protests at local, state and national levels. From time to time, in view of these agitation programs, the government has also made some important amendments, such as in 2016, the announcement of giving gratuity in NPS was made. In the year 2019, a provision was made for the option of choosing family pension under OPS (CCS Pension Rules 1972) in case of death of the employee during service. The government increased the employer's share in the contribution from 10% to 14%. But the protest of the employees did not stop.

Due to the protest of the employees, the government constituted a committee under the chairmanship of Finance Secretary Shri TV Somanathan after the general budget of the year 2023-24. After the submission of the committee's report, the government announced that a guaranteed pension would be given which would be 50% of the average basic pay of the last 12 months along with dearness allowance on completion of 25 years. Minimum pension of Rs 10,000 was announced but minimum family pension was not announced. This scheme will be known as UPS. The notification of this scheme is still awaited. After looking at the main features of this scheme, there is huge discontent among the employees because at the time of retirement, the employees will get a much lesser amount as compared to OPS. Out of the contribution amount made by the employee during the entire service period, only 10% will be provided as lump sum amount every 6 months. The hike that the pensioner gets in the old pension scheme on completion of 80, 85, 90, 95 and 100 years is also not there in UPS. **Madam**, the employee cannot settle for less than what he gets in OPS. Due to all the above reasons, there is huge discontent among the employees.

Madam, we want justice from you on the above two issues and demand that,

1. ***The eighth pay commission should be constituted without delay.***
2. ***NPS and UPS should be abolished and OPS must be implemented.***

Madam, to get these demands fulfilled, we will organize a public awareness fortnight from 15 January to 30 January.

The Confederation requests you to announce the immediate solution of the above two problems and please make the announcement in the general budget.

With Best Regards,

Yours Truly,

(SADHU SINGH)
Secretary General
Mob. 9415726924

Copy to:

1. The General Secretary, Bhartiya Mazdoor Sangh,
27, Pt. Deen Dayal Upadhyaya Marg.
(For kind information, please.)

दत्तोपंत ठेंगड़ी : सामाजिक समरसता के भाष्यकार

– साभार :
जीवन दर्शन

ज्येष्ठ तत्त्वचिंतक श्री दत्तात्रेय बापूजी उपाख्य दत्तोपंत ठेंगडी जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पाँच दशकों से अधिक समय तथा आजीवन प्रचारक थे। संघ विचारों को हृदय में धारण करने वाले, हिन्दू धर्म एवं जीवन दर्शन के आशय को समृद्ध बनाने वाले तथा आगे चलकर उस पर भाष्य करने वाले महान चिंतक थे। दूसरी ओर इसी अवधि में सारे देश में भ्रमण करते समय सामान्य जनमानस में हिन्दुत्व विचार जगाने का कार्य आप कर रहे थे। आपने कितनी बार पूरे देश की खाक छानी होगी. इसकी गिनती ही नहीं। साथ ही अपने पारदर्शी एवं आत्मीय आचरण द्वारा कितने लोगों को अपने संघ विचारों के साथ जोड़ दिया होगा, इसकी गिनती भी कौन करे? समूचा हिंदू समाज ही अपना ऐसी धारणा से वैचारिक मतभिन्नता के परे जाकर विभिन्न विचार प्रणालियों के साथ धर्मों के धुरीणों के साथ अपनत्व का नाता आपने जोड़ा। अपने असीम जनसंपर्क के माध्यम से जनमानस की नब्ज को सही ढंग से आप पहचानते थे तथा यथार्थ का समुचित भान आपको निरंतर हुआ करता था। विचारों की दृढ़ता तथा संगठन की रचना पर होने वाला पूरा अधिकार इनसे आप कृतिशील चिंतक माने गये। संघ के वैकल्पिक रूप में हिन्दुत्व दर्शन को तो आपने विकसित किया ही, पर उसके साथ संघ परिवार के अंतर्गत कितनी संस्थाओं को, संगठनों को सैद्धान्तिक बैठक आपने उपलब्ध करा दी। संघ परिवार में से कितने ही संगठन एवं संस्थाओं के आप प्रणेता एवं संस्थापक थे। मजदूर क्षेत्र में काम करने वाले 'भारतीय मजदूर संघ' नामक संगठन की आपने स्थापना की तथा देश में अव्वल दर्जे के और पहले क्रमांक के देशव्यापी मजदूर संगठन के रूप में उसे आगे बढ़ाया। शिक्षा एवं विक्षार्थी क्षेत्र में अपना प्रभाव निर्माण करने वाली 'अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद्', आर्थिक जनतंत्र, स्वाधीनता एवं स्वावलंबन आदि का पुरस्कार करने वाला 'स्वदेशी जागरण मंच' किसानों को अपनी ताकत का लिहाज करा देने वाला 'भारतीय किसान संघ', सभी धर्मों–पंथों का सूक्ष्म अध्ययन करके उनमें आपस में समझौते एवं सुलह के पुल बांधने वाला 'सर्वपंथ समादर मंच', कलाओं के मूल्य को जनमानस में जगाने वाली 'संस्कार भारती', आज देश की विषयसूची पर सबसे आगे होने वाला 'सामाजिक समरसता मंच' एक ही नहीं, तो कितने सारे नाम भी कितने गिने जायें! इन सभी संगठनों को अपनी असाधारण प्रतिभा द्वारा समाज में प्रस्थापित किया। उन्हें आगे बढ़ाया, उनका विकास किया। उन्हें तात्विक बैठक विकसित करा दी, इतना ही नहीं, तो कुशल संगठन के नाते उनकी संगठनात्मक रचना भी आपने करा दी। आज ये सभी संस्थाए–संगठन भारतीय समाज के निर्माण का तथा उनके स्तर को ऊपर उठाने का राष्ट्रव्यापी कार्य कर रहे हैं। राष्ट्रजीवन के ऊपर अपनी मुहर भी उन्होंने प्रभावी ढंग से लगाई है।

वैसे देखा जाये तो दत्तोपंतजी ग्रांथिक विद्वान नहीं थे अथवा ग्रंथालयीन संशोधक या अभ्यासक नहीं थे, फिर भी अपनी प्रगल्भ एवं चातुर्य बुद्धिमत्ता के बल पर अपनी वैचारिक धारणा को आपने व्यापक और मजबूत बना लिया था। अपने काफी कुछ व्यस्त दिनक्रम में भी आप कुछ पढ़ने के लिए फुर्सत निकाला करते थे। निरंतर हो रही यात्रा के दौरान कुछ न कुछ पढ़ने में मगन हुआ करते थे। उस दृष्टि से उनके हर एक प्रवास में चुनिन्दा ग्रंथ आपके साथ हमेशा होते थे। मराठी, हिंदी और अंग्रेजी सैकड़ों वैचारिक ग्रंथों का पठन ध्यानपूर्वक आपने किया। आपकी स्मरणशक्ति एवं चिंतन क्षमता असीम थी। उसके फलस्वरूप अपने लेखन तथा व्याख्यानों में अपने पढ़े हुए ग्रंथों के बहुत सारे फिर भी सही संदर्भ आप दिया करते थे। आपका प्रतिपादन मंडन तर्कशुद्ध, साधार तथा विचार समृद्ध हुआ करता था। आपके इस विशाल पठन द्वारा ही आपके जीवन संबंधी आकलन को समग्रता प्राप्त हुई थी।

आपके कितने सारे भाषण तर्कशुद्ध वैचारिक प्रतिपादन का सुनिश्चित–आकर्षक हुआ करता था। कोई वास्तुविशारद बढ़िया–आकर्षण गृहशिल्प का आरेखन करे अथवा कोई शिल्पकार अपनी अनोखी शैली से सुंदर सा मोहक शिल्प निर्माण करे, इस कोटि का प्रभावी आपका भाषण हुआ करता था। आपके बहुत से भाषण ग्रंथ बद्धहोकर प्रकाशित हुए हैं, उनमें इसके दर्शन हो सकते हैं। कितने ही ग्रंथों के लिए आपने प्रदीर्घ फिर भी विवेचक भूमिकायें लिखी हैं। उनके द्वारा आपके गाढ़े व्यासंग का परिचय होता है। 'पं. दीनदयाल उपाध्याय विचार दर्शन' शीर्षक के द्विखंडात्मक ग्रंथ के लिए आपने प्रदीर्घ प्रस्तावना लिखी है। प.पू. श्री गुरुजी गोलवळकर लिखित 'राष्ट्र' शीर्षक के ग्रंथ की प्रस्तावना आपने लिखी है। ये दोनों प्रस्तावनायें माने एक स्वतंत्र ग्रंथ की ही सामग्री जो है। दीनदयाल जी प्रतिपादित 'एकात्म मानव दर्शन' पर आपने किया हुआ विस्तृत भाष्य आपके चिंतन की परिधि का दर्शन कराता है। 'द थर्ड वे' और 'सामाजिक क्रांतिची वाटचाळ व डॉ. आम्बेडकर' ये आपके लिखे ग्रंथ, ये

वैचारिक क्षेत्र में मानो मील के पत्थर ही जो हैं। आपने हर एक उक्ति और कृति को राष्ट्रीय पुनरुत्थान के व्यापक संदर्भ का परिणाम प्राप्त हुआ था। सामाजिक एवं राष्ट्रीय समस्याओं का आपका आकलन, समाज एवं संस्कृति के बलस्थानों का आपको होने वाला ख्याल, इससे आपके लेखन में यथार्थ का 'भान और साथ–साथ आदर्श में लगन भी थी। आपके लेखन तथ भाषणों में से आपके विचार व्यूह का भेद बड़ी ही आसानी से होता चलता है तथा चिंतन के रूप में आपकी महानता झलकती ही चलती है। इस पृष्ठभूमि पर 'समरसता' इस विषय से संबंधित आपका गहरा चिंतन तथा श'सामाजिक क्रांतिजी वाटचाल व डॉ. अम्बेडकर' इस ग्रंथ में आपने रेखांकित किया हुआ समाज प्रबोधन का आलेख और संदर्भ में डॉ. आम्बेडकर जी की धारणा इन दो विषयों का ऊहापोह, इस लेख में किया जा रहा है।

'सामाजिक समरसता मंच' इस मंच की सन् 1983 में महाराष्ट्र में स्थापना हुई। उस वर्ष दिनांक 14 अप्रैल को डॉ. आम्बेडकर जी का जन्म दिन था और संयोगवश उसी दिन चैत्रशुक्ल प्रतिपदा थी माने संघ संस्थापक डॉ. हेडगेवार का भी जन्म दिन था। उस पवित्र पर्व का औचित्य साधते, पुणे में दिनांक 14 अप्रैल 1983 के दिन 'सामाजिक समरसता मंच' की स्थापना हुई। उसके पीछे दत्तोपंत ठेंगडी जी की प्रेरणा थी। उस दिन आयोजित विशाल सभा में दत्तोपंत जी ने 'समरसता' यह विषय सामाजिकता के आधार पर विस्तार से प्रतिपादित करने वाला बीज भाषण प्रस्तुत किया। तभी से महाराष्ट्र में मंच का कार्य आरम्भ हुआ। सभी, सम्मेलन, परिषद्, बैठकें, अभ्यासवर्ग आदि माध्यम द्वारा 'समरसता' इस विषय की बड़े पैमाने पर प्रगति होती चली। उसे कितने ही कृति कार्यक्रमों का साथ मिला। आज समरसता यह विषय देशव्यापक बन गया हैं और रा. स्व. संघ के कार्य में एक महत्वपूर्ण स्थान उसे प्राप्त हुआ हैं। इस समूचे मार्गक्रमण में दत्तोपंत का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण और मूल्यवान था। उसमें से सारभूत कुछ महत्वपूर्ण अंश को अब देखें।

समता शब्द के प्रचलित होते 'समरसता' इस कुछ अलग–सी संकल्पना को प्रस्तुति करना कहाँ तक जरूरी है, ऐसा सवाल मंच की स्थापना से ही पूछा जा रहा है। इस सवाल से यहाँ के विचार विश्व में किसी हदतक साली सी मची है। फिर भी कम से कम शुरू के काल में यह विषय संघ परिवार तक ही सीमित है, ऐसा विरोध करने वालों ने गृहित था, जिससे उनके विरोध में तीव्रता कहीं थी नहीं। और तो और सता' इस संकल्पना का सही अर्थ क्या होगा तथा सामाजिक ये उसकी व्यापकता कितनी कैसी और साथ ही सामाजिक अभिसरण दृष्टि से उसके परिणाम कितने व्यापक एवं दूरगामी होंगे, आदि अध्ययन करते केवल विरोध के लिए विरोध करने का सूत्र इस संकल्पना के विरोधकों ने अपनाया हुआ दिखाई देता है। फिर भी इस संदर्भ में संघ की धारणा बिल्कुल स्पष्ट होकर उस दृष्टि से उसकी कार्यवाही भी की जा रही है। यह धारणा सकारात्मक होकर समाज एकात्म एकरस होना आवश्यक है। संक्षेप में समरसता यह भारतीय राष्ट्रवाद का सामाजिक आशय है।

असल में संघ की धारणा ऐसी है कि समाज में दिखाइ दे रही विविधता यह एक स्वाभाविक विषय ही है। इसके विपरीत विषमता यह मानवनिर्मित है। विविधता यह एक स्वाभाविक के होते हुए भी अपनी विशेषताओं को कैसे निभाया जा सकता है तथा उन्हें निभाते हुये भी समाज में एकात्मता का समरसता का भाव कैसे निर्माण किया जा सकता है, यह हिन्दू संस्कृति ने और समाज ने पिछले हजारों वर्षों से दिखाया है। उसी सांस्कृतिक धरोहर का संघ प्रतिनिधित्व करता है और ध्यान देने लायक यही, कि 'समता' यह ऐहिक संकल्पना होने के साथ समाजधारणा के लिये वह आवश्यक हो, तो भी वह पर्याप्त नहीं होती। समता का साथ देने समाज में बंधुभाव एवं ममत्वबुद्धि अगर हो, तो समरसता का रसायन बन जाता है। इसलिये विराम समाजधारणा हेतु समता के साथ ही समरसता यह जीवनमूल्य भी आवश्यक होता है, ऐसी संघ की धारणा है। इसलिये समता अथवा समरसता इस प्रकार का अंतद्वंद्व या संघर्ष समाज में खड़ा करना उचित नहीं, संघ को भी वैसा कुछ अभिप्रेत नहीं।

किसी भी संकल्पना या मूल्यांकों को समाज द्वारा स्वीकृत कराना हो, तो उस प्रक्रिया का आरम्भ घर परिवार से ही करना चाहिये। इसलिये समरसता के इस भाव को पहले संघ में और संघपरिवार में दृढ़ बनाने पर बल देना सहज स्वाभाविक है। लेकिन यह विषय केवल संघ या संघ परिवार तक सीमित न होकर समूचा समाज यह उसका लक्ष्य है। 'समरसता' यह व्यक्ति के तथा समाज के मानसिक परिवर्तन के साथ जुड़ी हुई संकल्पना है। तभी तो वह धीमी गति से प्रदीर्घ काल तक चलने वाली प्रक्रिया है।

इस पृष्ठभूमि पर 'समता' एवं 'समरसता' इन संकल्पनाओं का समुचित आकलन होना आवश्यक है। लगभग दो ढाई सौ बरसों पहले हुई फ्रेंच राज्यक्रांति के दौरान 'स्वतंत्रता', समता एवं बंधुता' इस तत्वत्रयी का बीजारोपण हुआ। इस राज्यक्रांति की वैचारिक पृष्ठभूमि तैयार करने का कार्य हॉब्ज, लॉक तथा रूसो, व्हॉल्टेअर इन दर्शनिकों ने किया। उनके तत्वचिंतन में से इस तत्वत्रयी का नवनीत हाथ लगा। उनसे प्राप्त हुई प्रेरणा से फ्रान्स की राज्यक्रांति हुई। समता यह इन तीन संकल्पनाओं में से एक है। वह मूलतः ऐहिक एवं भौतिक रूप की है। उसमें निहित

सूत्र आम तौर पर सामाजिक विषमता के विरोध में है। इस विषमता के भी कितने ही पहलू हैं। आम तौर पर विषमता हम अनुभव करते हैं, वह होती है आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक क्षेत्रों में, साथ ही प्रकृति प्रदत्त स्वभाव एवं संगोपन सिद्ध रूप में तथा जीवन व्यवहार में से अभिव्यक्ति में नैतिक एवं सांस्कृतिक आयामों को इस संकल्पना के साथ जोड़ना जरूरी है। इस पर पाश्चात्य चिंतकों ने गौर किया हुआ दिखाई नहीं देता और बात ऐसी, कि सभी क्षेत्रों हर हालत में समता प्रस्थापित होना क्या आवश्यक तथा संभव भी होगा, यह भी एक सवाल है। एक सुविख्यात ब्रिटिश चिंतक अपने निबंध में कहते हैं, 'सभी को पूर्ण तथा समता के आर्थिक स्तर पर लाकर आर्थिक समता प्रस्थापित करना यह शायद असम्भव ही होगा तथा वैसा करना यह शायद हानिकारक एवं अव्यवहार्य भी होगा।' आर्थिक समता के संदर्भ में जो सत्य है, वह कुल मिलाकर समता इस संकल्पना के संबंध में ही सत्य है। उन्हें जो समता अभिनेत्री है. वह अवसर उपलब्धि की समानता में है। भारतीय चिंतक डॉ. अम्बेडकर कहते हैं, 'स्वतंत्रता, समता और बंधुता ये तत्व मानो यह त्रिमूर्ति है। उनमें से हर एक अलग स्वतंत्र है, ऐसा न माना जाये। इन तीन संकल्पनाओं में से किसी एक ने दूसरी को अगर तलाक दिया, तो जनतंत्र के प्रयोजन की ही हार होगी।' इन संकल्पनाओं के परस्परावलंबित्व को अम्बेडकर जी ने बिल्कुल समुचित शब्दों में प्रतिपादित किया है। इसलिये उनका यह भाष्य बड़ा ही महत्वपूर्ण है।

समाज के सभी क्षेत्रों में सिर्फ समता प्रस्थापित करने से समाज के समक्ष सभी समस्याएयें हल होंगी ऐसा उसका आशय नहीं। उस हेतु समता इस संकल्पना के साथ भावात्मकता को जोड़ना चाहिये। यह भावात्मकता मानो हर एक व्यक्ति के मन में आपस में हर दूसरे को लेकर होने वाला, आदर, प्रेम, आत्मीयता एवं बंधुभाव! फ्रेंच राज्यक्रांति भी तत्वत्रयी में समता का जैसा कि निर्देश है, वैसा बंधुता का भी स्वतंत्र निर्देश किया गया है। इसके माने यही कि पाश्चात्यों की 'समता' इस संकल्पना में 'बंधुभाव' का समावेश नहीं होता। वैसा अगर होता, तो 'बंधुता' इस संकल्पना का स्वतंत्र अलग निर्देश क्यों किया जाता ? इसी में से 'समरसता' इस संकल्पना की सीमायें स्पष्ट होती हैं। इसे एक दृष्टान्न द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। पुरानेजमाने से चलते आये अस्पृश्य और दलित समाज को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षणिक क्षेत्र में अन्य समाज के समान केवल बराबरी का स्थान और अवसर प्राप्त होने से क्या उनकी सभी समस्यायें हल हो पायेंगी? जो समस्यायें आत्मसम्मान के साथ, सामाजिक प्रतिष्ठा के साथ जुड़ी हुई हैं, स्वीकार्यता के साथ, सामाजिक अभिसरण के साथ जुड़ी हुई हैं, उन्हें बंधुभाव को आत्मीय भाव के साथ जोड़ना आवश्यक है। इसलिये समता के समर्थकों द्वारा समता अथवा समरसता ऐसा द्वंद्व समाज में निर्माण करना उन्हें शोभा न देगा।

इस पृष्ठभूमि पर 'समरसता' इस संकल्पना पर हम सोचें! समता को समता का जब साथ मिलता है, तब 'समरसता' निर्माण होती है। 'समरसता' संकल्पना समता को अस्वीकार नहीं करती, तो समता के अधूरापन का ख्याल कर, उसे ममता का साथ मिलना चाहिये, इसे अधोरेखित करती है। समाज में से सभी घटकों में आपस में एक–दूसरे के लिए बंधुभाव निर्माण हुआ, तो ही समता की यात्रा समरसता की दिशा में आगे बढ़ सकती है। 'समरसता' का भाव समूचे समाज में स्थायी बन गया, तो स्वाभाविक विविधता में भी एकता, एकात्मता अनुभव होने लगती है। समाज में स्थिर बने ऊँच–नीच भाव झड़ने लगते हैं। इसीलिये समता जितना ही समरसता के लिए आग्रह होना चाहिये। एकता यह सामाजिक जीवन का मूल्य होता है। उसे प्रस्थापित करने समरसता को समर्थन देना आवश्यक है। उसी के द्वारा जातिभाव के अभिनिवेश का विकास होगा और एकात्म, एकरस एवं सुसंगठित समाज निर्माण का मार्ग प्रशस्त होगा इसमें कोई संदेह नहीं।

समरसता यह केवल बौद्धिक एवं सैद्धान्तिक चर्चा का विषय नहीं। वह प्रत्यक्ष जीवन में आचरण करने का, व्यवहार का विषय है। इसीलिये उसका बुद्धि के साथ भावना द्वारा भी स्वीकार होना चाहिये। तभी जाकर उसका प्रत्यक्ष जीवन में आचरण हो पायेगा। इस प्रकार समरसता के माध्यम से समाज में उचित होने वाला मानसिक परिवर्तन लाना तथा उसके अनुसार प्रत्यक्ष जीवन में आचरण होना इसका अन्य कोई विकल्प नहीं!

इस समरसता को जनमानस में दृढ़ बनाना यह तो एक लम्बा रास्ता ही है, परन्तु वही एकमात्र मार्ग होने से सबसे नजदीक का मार्ग है। उसका विशेष यही, कि प्रत्यक्ष आचरण करने की सर्वाधिक संभावना होने वाला वह मार्ग है। इसलिए 'समरसता' इस विषय को लेकर केवल तात्विक माथापच्ची न करते, समाज में समता के साथ ही समरसता कैसे जौर किस मार्ग से लाई जा सके, यह समाजसुधारकों के समक्ष सबसे बड़ा आहवान है। इस आह्वान को कैसे निभाया जाता, किस गति से उसे निभाया जाता, इस पर इस राष्ट्र का भविष्य निर्भर करता है।

समरसता, समता इन विषयों के संदर्भ में दत्तोपंत जी की विचार प्रणाली कैसी थी, यह विशद हो, इस उद्देश्य से आपने कई बार किये हुये प्रतिपादन को साररूप में यहाँ प्रस्तुत किया है। दत्तोपंत जी का गहरा अध्ययन, आपका किसी भी विषय से

संबंधित चिंतन कितना गहरा, कितना समाज निष्ठ था, इसकी प्रतीति करा देने वाला यह विचार व्यूह है। किसी भी सामाजिक समस्या की जड़ तक सीधे जा पहुँचना, उस समस्या का यथोचित आकलन करा लेना, उसके रूप स्वरूप का सर्वांग परिपूर्ण परिचय करा लेना, तथा उस दिशा में आगे बढ़ते उसका उत्तर खोज निकालना, ऐसी किसी भी समस्या का सामना करने की आपकी शैली थी। समस्या कैसी भी जटिल क्यों न हो, तो भी शांतचित्त होकर उस उलझन को सुलझाये बगैर कोई हल निकलेगा नहीं, ऐसी आपकी धारणा थी। आज समाज के समक्ष जो भी समस्यायें उभर आई हैं, वे सभी समरसता के अभाव में से निर्माण हुई हैं। इसीलिये समाज में समरसता का भाग जागृत करना यही उसका इलाज हो सकता है, ऐसी इस संदर्भ में आपकी धारणा थी।

अपने देहावसान के कुछ सप्ताह पहले दत्तोपंत जी ने 'सामाजिक क्रांतिची वाटचाल व डॉ. अम्बेडकर' यह बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखकर पूरा किया। तीन सौ पृष्ठों का मूल विषय का विश्लेषण और अगले पृष्ठों में वीर परिशिष्ट, ऐसी इस ग्रंथ की रचना है। अपने समूचे जीवन भर सारसर्वस्व इस ग्रंथके रूप में आपने अध्येताओं के साथ सक्षम रखा है। दत्तोपंत जी को आंबेडकर जी के जीवन के अंतिम 5–6 बरसों में उनके निकट सहवास का सौभाग्य मिला था। डॉ. अम्बेडकर जी के जीवन एवं कार्य का सार तथा उसके समाज के ऊपर हो रहे दूरगामी परिणाम, इन्हें लेकर आपने निरंतर चिंतन किया था। इस ग्रंथ में आपने सौ से अधिक पाश्चात्य एवं भारतीय चिंतकों और लेखकों के संदर्भ दिये हैं। उसकी व्यापकता को देखते अपने भरेपूरे व्यस्त जीवनक्रम के दौरान भी आपने अपने लेखन के हेतु कितनी–कैसी पूर्व तैयारी की थी, यह दिखाई देता है। इस ग्रंथ का दोहरा महत्व है। रा.स्व. संघ के विचारों के भाष्यकार के रूप में, उन्नीसवीं सदी में हुये समाज प्रबोधन आंदोलन का मूल्यमापन एवं विश्लेशण आपने किया है और तो और सामाजिक क्रांति के हो रहे मार्गक्रमण की पृष्ठभूमि पर आपने बाबासाहब के व्यक्तित्व में तथा विचारविश्व में अवगाहन किया है। इस दृष्टि से इस ग्रंथ का रूपस्वरूप कुछ अनोखा ही बना है। प्रतिपाद्य विषय के संदर्भ में बाबासाहब के जीवन में से महत्वपूर्ण घटनाओं का जितना परामर्श लेना जरूरी है, उतना ही लिया हुआ दिखाई देता है। वैसे तो लेखक का मूल उद्देश्य बाबासाहब की मूल धारणा और वैचारिक दृष्टिकोण इनका चिकित्सकीय अध्ययन करने का है। सही मायने में यह डॉ. आंबेडकर की रूढ़ जीवनी नहीं तथा केवल व्यक्ति विमर्श भी नहीं, उसका स्वरूप विचार विमर्श का है।

महाराष्ट्र में प्रबोधन पर्व का शुभारंभ सन् 1832 में आचार्य बालशास्त्री जांभेकर जी द्वारा प्रथम प्रकाशित 'दर्पण' नामक मराठी अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका से हुआ। तब तक अंग्रेजों ने अपनी सत्ता को स्थायी बनाना आरम्भ किया था। पाश्चात्य ढंग की शिक्षा, आधुनिक प्रशासन यंत्रणा और वैज्ञानिक सुधारों का प्रयोग आदि साधनों के माध्यम से अंग्रेजों ने यहाँ परिवर्तन प्रक्रिया आरम्भ की। पिछली कई सदियाँ पराधीनता में तथा अराजक सदृश्य परिस्थिति में गुजारने वाले भारतीयों के लिए यह परिवर्तन कुछ नया ही जो था। 19वीं सदी की पहली कम से कम 4–5 पीढ़ियाँ, यस परिवर्तन से अभिभूत हो गई थीं। इतना ही नहीं तो अंग्रेजी राज को ये ईश्वरीय वरदान ही मानते थे। अंग्रेजोंकी आधुनिकता के कारण ही इस प्रक्रिया का मूल्यमापन करते हुये दत्तोपंत जी कहते हैं, श्इस प्राचीन समाज की सांस्कृतिक विरासत मिट्टी में मिले और अंग्रेजी से पूरी तरह प्रभावित समाज यहाँ निर्माण हो, यहाँ तक कि अंग्रेजों ने आरम्भ किये आधुनिकीकरण के इरादे उन्नीसवीं सदी के प्रबोधन पर्व में चार प्रमुख परिवर्तन प्रवाह हैं, ऐसा लेखक का विश्लेषण है और उसकी यथार्थ मीमांसा भी आपने की है। पहला नया, रानडे का अध्यात्मनिष्ठ, उदार मतवादी, सर्वांगीण सुधारवाद नरम दल के इस प्रवाह में बाल शास्त्री जांभेकर, लोकहितवादी रानडे, गोपाल कृष्ण गोखले का समावेश होता है। दूसरा विष्णुशास्त्री चिपलूणकर और लो. तिलक इनका सामाजिक सुधारों की अपेक्षा राजनीतिक स्वाधीनता प्राप्ति का महत्व जताने वाला परम्परानिष्ठ, गरम आक्रमण भावनात्मक तथा राष्ट्रवाद। तीसरा गो. ग. आगरकर का इहवादी विज्ञाननिष्ठ व्यक्तिवादी सुधारवाद। इन तीनों प्रवाहों से अलग होकर बहने वाला म. फुले का बहुजन एवं दलित समाज के उत्थान का क्रांतिकारी सुधारवाद यह चौथा प्रवाह।

पहले तीनों प्रवाहों पर भाष्य करते हुये लेखक कहते हैं, 'इन तीनों प्रवाहों में सामाजिक समता, जातिनिर्मूलन, अस्पृश्यतानिवारण ये विषय केवल तात्विक स्तर पर चर्चा के रूप में ही आगे बढ़ाये गये। इन सभी को अभिप्रेत प्रत्यक्ष सुधारों का आशय व्यक्तिगत पारिवारिक स्तर पर उच्चवर्गीय समाज के घेरे के बाहर पहुँचा ही नहीं। परिवर्तन के ये प्रवाह वास्तव में कार्य की दृष्टि से देखा जाये तो केवल समाज के मध्यवर्गीय स्तर से ही जुड़े हुये सीमित रहे। इस वैचारिक आंदोलन को कृतिशीलता का मजबूल साथ मिला नहीं क्योंकि यह उन प्रवाहों की सीमा ही जो ठहरी।'

इन सीमाओं को छेद देते हुये तथाकथित उच्चवर्णीय समाज के सुधारों की परिधि के बाहर चलकर समाज जीवन के बिल्कुल गहरे स्तर पर होने वाले समाज घटकों के सुधार का सर्व प्रथम क्रियाशील गहरे स्तर पर होने वाले समाज

घटकों के सुधार का सर्व प्रथम क्रियाशील समर्थन जिन्होंने किया, वे क्रियाशील सुधारक क्रांति के अग्रदूत ने इन शब्दों में किया है। म. फूले ने अपने वैचारिक आंदोलन के माध्यम से समाज जीवन का आमूलाग्र मंथन किया। इस क्रांति को आंदोलन का रूप दिया। सुधारवाद से क्रांतिशीलता को जोड़ दिया। ''अपनी समाज रचना के अंतर्गत जन्मजात ऊँच–नीच, ऊँचनीच भाव एवं अस्पृश्यता ये ही सामाजिक विषमता के मुख्य कारण हैं।'' ऐसा उनका विश्लेषण था। ऐसा करने के लिये समाज के जो अंग उत्तरदायी थे, उनके ऊपर उन्होंने करोड़ टीका–टिप्पणी की। उन्होंने शूद्रातिशूद्रों की लड़कियों के लिये पहली पाठशाला खोली। पाँव फिसली हुई महिलाओं के लिये प्रसूतिगृह और गर्भालय खोला। अपने घर के सामने वाला पानी का हौज अस्पृश्यों सहित समूचे समाज के लिए खुला कर दिया। किसानों के सम्मेलन आयोजित किये, ब्राह्मणों के दमनकारी दाँवपेच खुल कर समझाये। सार्वत्रिक और निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा के सिद्धान्त का समर्थन करते 'झरना सिद्धान्त' को अस्वीकार किया। 'सत्यशोधक समाज स्थापित करते अपने कार्य को संस्थात्मक रूप दिलाया तथा समाजधारणा के लिये धर्म की होने वाली जरूरत को देखते परिष्कृत रूप में श्सार्वजनिक सत्यधर्म' शीर्षक से नई रचना करने का प्रयास उन्होंने किया। नारी प्रतिष्ठा के संदर्भ में उन्होंने व्यक्त किये हुये विचार आज भी क्रांतिकारी दिखाई देते हैं। उनके लेखन और वाणी में होने वाली कठोरता की अपेक्षा तथा ऊजड़ अभिव्यक्ति की अपेक्षा होने वाले सत्व को, आशय को और मूलगामी चिंतन को अगर महत्वपूर्ण माना, तो म. फूले की महानता का सही परिचय हो पायेगा।

इसके पश्चात् दत्तोपंतजी ने सन् 1890 से 1920 इस संधिकाल के दौरान सामाजिक क्रांति के मार्गक्रमण का संक्षेप में समालोचना की है।

सत्यशोधक समाज के मूल तत्व का महात्मा फुले के अनुयायियों को सही आकलन न होने से ब्राह्मण–ब्राह्मणेत्तर आंदोलन में हुआ परिवर्तन, 'सार्वजनिक सत्यधर्म' का हुआ विस्मरण, इन्हें देखते शिष्यों ने ही गुरु को पराजित किया, ऐसे निष्कर्ष पर लेखक पहुँचे हैं। फिर भी इस संधि काल के दैरान इस प्रवाह को बहता रखने के लिये कोल्हापुर के छत्रपति शाहू महाराज, बड़ौदा नरेश सयाजीराव गायकवाड़, महर्षि विठ्ठल राम जी शिंदे आदि ने किये हुये कार्य को दाद देते हुये, उसका महत्व भी विशद किया है। अम्बेडकर क्रांति की यात्रा का रूप ऐसा ही कुछ थाः

उस समय की सामाजिक परिस्थिति की ओर देखते, बाबासाहब ने अपने बचपन में दिल दहलाने वाली अस्पृश्यता जो अनुभव की, वह शायद कुछ खास मानी न जाये, तो भी इंग्लैंड–अमेरिका के विश्वविद्यालयक से एक से बढ़कर एक उपाधियाँ पाकर भारत लौटे हुए बाबा साहब को जो भी कुछ भुगतना पड़ा, उसे देखते विद्वताप्राप्त बाबासाहब की ओर देखने के सवर्णों के दृष्टिकोण में तनिक भी परिवर्तन–सुधार हुआ नहीं. अस्पृश्यता के अपमानास्पद भोग उन्हें भुगतने पड़े, यह बड़ी ही दुःख देने वाली शर्मनाक बात है। बाबासाहब ने पाई हुई उपाधियाँ, उसमें होने वाले विषयों की व्यापकता, उस हेतु उन्होंने किया हुआ प्रचंड वाचन–पठन, सहे हुये कष्ट, हर एक उपाधि हेतु लिखा हुआ विद्यमान ग्रंथ, ऐसा बाबासाहब के ज्ञानार्जन का इतिहास युवा वर्ग को प्रेरणा पाने के लिए पढ़ना चाहिये।

सन् 1923 में भारत लौटने के पश्चात् सन् 1935 में येवला में धर्मान्तरण घोषित करने तक की बाबासाहब के जीवन की कालावधि रचनात्मक कार्य की, संघर्ष की, आंदोलन भरी ही रही। उनका प्रत्येक विचार एवं कृति एक ओर दलित समाज के उद्धार हेतु थी, तो दूसरी ओर हिंदू धर्म की आचार प्रणाली पर प्रहार करते इस समाज को एकात्म. एकरस बनाना यह उनका जीवित कार्य था। उनकी भूमिका श्हिंदू धर्म सुधारकश थी। वे खुद को 'प्रॉटेस्टंट हिंद' अथवा 'नॉन कन्फर्मिस्ट हिंद' कहा करते थे। पहले 'मूकनायक' और उसके बाद 'बहिष्कृत भारत' इन नियतकालिकों में जातिव्यवस्था, ऊँच–नीच, अस्पृश्यता तथा सामाजिक विषमता आदि पर कठोर आघात किया करते, हिन्दुओं के आचारधर्म पर कठोर टिप्पणियाँ करते चले। पहले श्बहिष्कृत हितकारिणी सभाश और बाद में श्समाज–समता संघश इनकी स्थापना करते, समाज प्रबोधन के आंदोलन को उन्होंने संस्थात्मक रूप दिलवाया। महाड के चवदार तालाब का सत्याग्रह, पुणे में पर्वती और नाशिक का कालाराम मंदिर–वहाँ के मंदिर प्रवेश सत्याग्रह, स्थान–स्थान पर आयोजित अस्पृश्यता परिषदें, आदि सभी प्रयासों द्वारा दलित मुक्ति आंदोलन को उन्होंने विभिन्न आयाम दिलवाये। महाड परिषद में श्हर एक हिंदू के जन्मसिद्ध अधिकारों का घोषणापत्रश प्रस्तुत किया। श्ॲनिहिलेशन ऑफ कास्टश नामक ग्रंथ में श्हिंदू धर्म में सुधारश के मार्ग अधोरेखित किये। उनके सभी आंदोलनों का केंद्रबिंदु श्दलित मुक्तिश तथा श्हिन्दू धर्म में सुधारश यही था। यहाँ के सवर्ण हिंदू समाज को इसका आकलन हुआ नहीं। तब जाकर उन्होंने हताश होकर श्दुर्भाग्य से मैं अस्पृश्य समाज में पैदा हुआ। यह तो मेरा अपराध नहीं, फिर भी मरते समय मैं श्हिन्दू होकर मरूँगा नहींश, ऐसा घोषित किया। वास्तव में उसके 21 वर्ष बाद उन्होंने धर्मांतरण किया, क्योंकि तबतक हिंदू समाज की मानसिकता में जरा भी परिवर्तन आया नहीं था, इसे वे देख रहे थे। इस संदर्भ में 'टाइम्स ऑफ इंडिया' में प्रकाशित पत्र में

उन्होंने लिखा था, श्अस्पृश्यों के धर्मांतरण से आम तौर पर देश के ऊपर कौन–सा असर होगा, यह गौर करने लायक है। यदि वे मुसलमान धर्म में या ईसाई धर्म में गये, तो वे अराष्ट्रीय बन जायेंगे। वे अगर मुसलमान बन गये, तो मुसलमानों की संख्या दुगनी हो जायेगी और उससे उनकी प्रभुसत्ता बढ़ेगी। वे अगर ईसाई बन गये, तो ईसाइयों की संख्या 5–6 करोड़ होगी। उसके परिणामस्वरूप ब्रिटिश शासन की इस देश के ऊपर की पकड़ का मजबूत होना आसान होगा। इसके विपरीत वे अगर सिक्ख बने, तो उससे हिंदुस्थान के भविष्य की कहीं हानि हो पायेगी... वे अंतर्राष्ट्रीय न बनेंगी।श आगे चलकर बाबासाहब ने बौद्ध धर्म ● का गहरा अध्ययन किया और उस धर्म में वे प्रविष्ट हुये। इस प्रकार सब ● कुछ तय करते समय उनकी धारणा हिंदूहित की तथा राष्ट्रहित की ही रही, इस पर तथाकथित सवर्ण समाज ने गंभीरता से कहीं गौर ही किया नहीं। बाबासाहब कहते हैं, ''जो धर्म इस देश की प्राचीन संस्कृति को हानि पहुँचायेगा अथवा अस्पृश्यों को अंतराष्ट्रीय बना देगा, ऐसे धर्म को हरगिज हम स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि इस देश के इतिहास में 'विध्वंसक' के रूप में अपना नाम गिना जाये, ऐसा मैं नहीं चाहता''। 'बाबासाहब की महानता और साथ ही धर्मांतरण के पीछे होने वाली प्रखर देशभक्ति और विशुद्ध समाजनिष्ठा, क्या इन सभी घटनाओं की ओर धारणा द्वारा अधोरेखित नहीं होती? दत्तोपंत ठेंगडी जी को डॉ. अम्बेडकर जी के सहवास का प्रदीर्घ काल तक लाभ होने से सामाजिक क्रांति का महत्वपूर्ण चरण होने वाले बाबासाहब की धर्मांतरण संबंध में होने वाली वैचारिक धारणा का तथा मानसिक आंदोलन का पारदर्शी चित्र उन्होंने इस ग्रंथ में रेखांकित किया है।

बाबा साहब ने अर्थविषयक गहरे चिंतन के आधार पर विद्वत्मान्य ग्रंथों का लेखन किया, फिर भी ग्रांथिक विद्वान अर्थतज्ञ के रूप में आपको स्वीकार करने के लिए राजी नहीं, उनके विचारों की कहीं दाद भी देना नहीं चाहते, इसका दत्तोपंतजी को खेद था। बाबासाहब के राजनीतिक एवं वैधानिक जीवन का तथा संविधानकार के रूप में उन्होंने किये हुये 'भीम' कार्य का चिकित्सक समालोचन दत्तोपंतजी ने किया है। 'बाबासाहब और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ' इस अध्याय में कितने ही नये विषयों पर उन्होंने प्रकाश डाला है। बाबासाहब को अपने समाज के संदर्भमें जो भी चिंतायें सता रही थीं, उनका भी चित्रण मार्मिक संदर्भ देते हुये दत्तोपंत जी ने किया है। बाबासाहब एक युगपुरूष ही थे तथा जैसे ही काल बीतता चलेगा, वैसे ही उनके कार्य की महानता जनमानस पर अंकित होगी, ऐसा विश्वास दत्तोपंत प्रकट करते हैं। आपके इस विश्वास को सार्थक करने वाला अभ्यासपूर्ण ग्रंथ माने 'सामाजिक क्रांतिची वाटचाल व डॉ. अम्बेडकर' ऐसा कहा जाता है। इसके फलस्वरूप दत्तोपंत जी केवल सामाजिक क्रांति के ही न होकर डॉ. अम्बेडकर जी के विचारविश्व के भाष्यकार के रूप में हमारे समक्ष व्यक्त होते हैं, यही आपका महत्वपूर्ण योगदान है।

❐

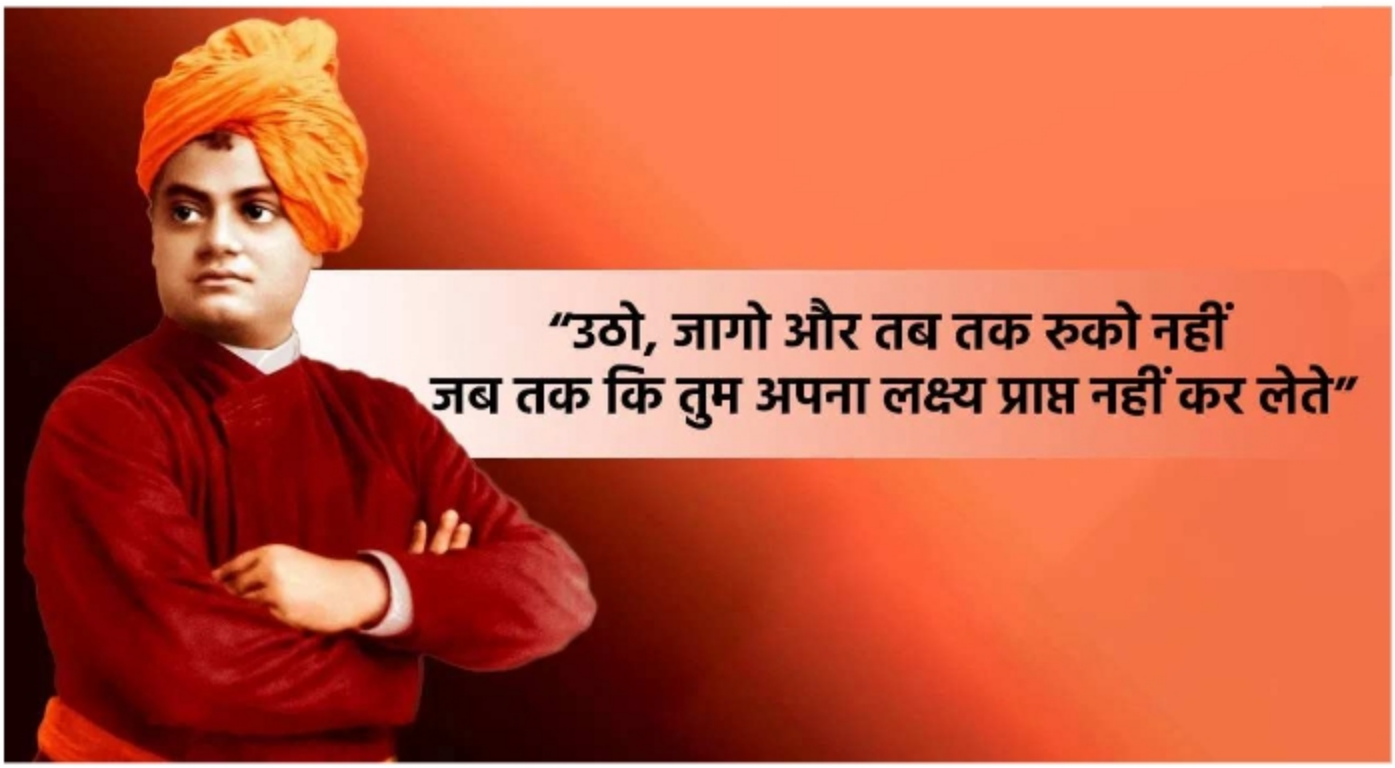

Government ORDERS

F. No. 36012/ 1/2020-Estt.(Res-II) Government of India Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions Department of Personnel and Training Dated : 7th Jan. 2025

Sub.: Reservation in promotion with Persons with Benchmark Disabilities- grant of notional promotion w.e.f. 30.-i.2016 onwards- reg.

The undersigned is directed to refer to this Department's OM No. 36012/ 1/2020-Estt.(Res-II), dated 28.12.2023 (copy enclosed) and subsequent reminder OM of even number, dated 9.10.2024 (copy enclosed) requesting all the Ministries/Departments to undertake the exercise regarding ascertaining the requirement of creation of supernumerary posts for the purpose of granting the notional benefit of reservation in promotion to PwBD employees during the period from 30.6.2016 to 16.5.2022 in terms of DoPT O.M. dated 17.5.2022 and O.M. dated 28.12.2023 and submit the proposal to DoPT.

In response thereto, proposals are still awaited from some of the Ministries/Departments. Ministries/Departments are once again requested to look into the matter on priority and carry out the requisite exercise of creation of supernumerary posts for extending the notional benefit of reservation in promotion to eligible PwBDs with effect from 30.6.2016 onwards and accordingly submit the proposal to DoPT in the prescribed proforma (Annexure-1) with the approval of the concerned Hon'ble Minister /MoS to this Department at an early date. ❐

No. 36012/1/2020-Estt (Res-II) Government of India Ministry-of Personnel, Public Grievances &. Pensions Department of Personnel & Training Dated : 28th Dec. 2023

Sub.: Reservation in promotion to Persons with Benchmark Disabilities (PwBDs) regarding.

The undersigned is directed to say that the Hon'ble Supreme Court, vide its Judgement dated 30.6.2016, in the WP(C) No. 521/2008, titled 'Rajeev Kumar Gupta Vs. UOI, had directed the Government to extend three percent reservation to PWD in all identified posts in Group A and B, irrespective of the mode of filling up of such posts. However, subsequently the Hon'ble Supreme court, vide its Order dated 3.2.2017, in the Civil Appeal No. 1567/2017 titled 'Siddaraju Vs. State of Karnataka & ORS' referred to the prohibition made against reservation in promotion as laid down by the majority in Indra Sawhney & Others v. Union of India & Others (1992) and observed and held that its Judgement dated 30.6.2016 in Rajeev Kumar Gupta needed to be considered by a larger Bench. However, the Hon'ble Supreme Court finally disposed of the Siddaraju matter vide its Judgement dated 14.1.2020 and held that its Judgement in Rajeev Kumar Gupta would bind the Union and State Goverment and it must be strictly followed.

2. However, the Union of India needed some clarification with regard to the implementation of the HOn'ble Supreme Court Judgement dated 30.6.2016 and 14.1.2020, and, therefore, Application for clarifiation was filed by the UOI before the Hon'ble Supremem Court seeking clarification which inter all included whether the vacancies for promotion for Pwds would be computed only on the basis of the vacancies against the identified posts or against the vacancies in both identified and non-identified posts and whether the Judgement dated 14.1.2020 needs to be implemented on the basis of PwD Act. 1995 or RPWD Act. 2016, Hon'ble Supreme Court disposed of this Application for clarification vide its Order dated 28.9.2021 directing the Government of India to issue instructions regarding reservation in promotion as provided in section 34 of the RPwD Act, 2016.

3. Proviso to section 34 of the RPWD Act, 2016 provides that the reservation in promotion shall be in accordance with such instructions as are issued by the appropriate Government from time to time. Acordingly, DoPT vide its OM of even number dated 17.5.2022 issued detailed instructions for extending the benefit of reservation in promotion to PwDs up to the lowest rung of Group 'A' in posts and services under the Central Government. This OM is effective with effect from the date of its issue i.e. 17.5.2022.

4. However, in a contempt Petition (Civil) No. 873/2023 filed by Shri S. S. Sundaram against Department of Revenue, the Hon'ble Supreme Court vide its order dated 18.7.2023 has directed "Though it is pointed out that the Judgement of this Court of which breach is alleged, has been compiled with effect from 15.7.2023, the fact remains that the judgement is of 30.6.2016 directing the respomdents to implement the 1995 Act. Therefore, the repondent will have to consider of giving at least notional promotion to those who are eligible from an earlier date."

5. The aforesaid direction dated 18.7.2023 of the Hon'ble Supreme Court has been considered in consultation with the Department of Legal Affairs and it

has been decided to grant notional promotions to the PwD candidated w.e.f. 30.6.2016 as under:

(i) Pwd employees in post and services of the Central Government, will be considered for grant of the benefit of reservation in promotion up to the lowest rung of Group 'A' on notional basis w.e.f. 30.6.2016 subject to their fulfillment of the eligibility conditions as laid down in the DoPT OM of even number dated 17.5.2022 regarding reservation in promotion to PwDs. However, the extent of reservation in promotion may be in accordance with the relevant provisions contained in the PwDAct. 1995 and RPWD Act. 2016. Further, this benefit may be extended after holding Review DPC as per the extant instructions issued by DoPT on the subject. In case the PwD employees are found eligible and suitable for promotion from any date subsequent to 30.6.2016, then the benefit of reservation in promotion. This promotion on notional basis includes promotion on seniority quota as well as Departmental Examination/Departmental Competitive Examination, which has already been held during the period from 30.6.2016 to 16.5.2022, the eligibility pf the PwD candidated may be assessed on the basis of their performance in the said examination. The concerned Administrative Authorities are given discretion to consider holding of special examination for assessing the suitability or eligibility of PwD employees for such Departmental Competitive Examination.

(ii) Extending the benefit of reservation in promotion to the PwD employees on notional basis between 30.6.2016 and actual assumption of the charge of the post may affect the inter-se-seniority of the officials in various grades. Due to this, there may be cases in which some officials may have to be placed in a select list/seniority list, subsequent to the year of their existing/present seniority list/select list. This may have a chain effect as it may result un revision in seniority lists in subsequent years in many cases which may cause administrative inconvenience. In order to avoid such situation, supernumerary posts may be created to adjust the lien of such PwD employees with effect from the date on or after 30.6.2016, when they become eligible to get the benefit of reservation in promotion, till the availibility of vacancy in which the promotion os to be made or till they vacate the posts on their retirement, further promotion etc. whichever is earlier.

(iv) The creation of supernumerary post, as stated above, will be personal to the PwD employee who is given the benefit of reservation in promotion on notional basis and such supernumerary post will stand abolished on the date when such PwD employee is adjusted against available vacancy in the grade in which the promotion is given or when that PwD employee cacates the post on his/her retirement, further promotion etc., whichever is earlier.

(v) Ministries/Departments are advised to undertake an exercise to ascertain the requirement of supernumerary posts required by them and submit the proposal for creation of posts to the Department of Expenditure through DopT. Such proposal shall contain the proposal in respect of the entire Department/Ministry and the proposal in piecemeal shall not be accepted. A certificate to the effect that the proposal is complete in all respects and the requirement of creation of supernumerary poets has been projected is respect of the entire Department may also be furnished along with the proposal. Further each proposal shall have the concurrence of the Liaison Officer for PwDs of the Department/Ministry concerned and shall be forwarded with the approval of the secretary of the Administrative Department/Ministry.

(vi) It is clarified that the benefit of notional promotion, as proposed above, shall not adversely affect those PwD candidates who have already been granted the benefit of reservation in promotion in personam in pursuance of the Orders/Judgement of various Courts of Law.

6. This issues with the approval of Department of Expenditure conveyed vide their ID Note No.7(1)/E. Coord.I/2017 Part (V) dated 12.12.2023. ❐

No. 36012/1/2020-Estt (Res-II) Government of India Ministry-of Personnel, Public Grievances &. Pensions Department of Personnel & Training Dated : 9th Oct. 2024

Sub.: Reservation in promotion with Persons with Benchmark Disabilities- grant of notional promotion w.e.f. 30.6.2016- reg.

The undersigned is directed to say that this Department, vide its OM of even . number, dated 28.12.2023 (copy enclosed) had informed all the Ministries/ Departments that in pursuance of the Hon'ble Supreme Court judgement in Rajeev Kumar Gupta Case, detailed instructions regarding grant of benefit of reservation in promotion to PwBDs upto the lowest rung of Group 'A' have been issued. Further, in

pursuance of the Hon'ble Supreme Court Order dated 18.7.2023 in the Contempt Petition (Civil) No. 873/2023 titled S.S.Sundram vs. Shri Vivek Johri & Anr, this Department, vide OM dated 28.12.2023 extended the benefit of reservation in promotion on notional basis w.e.f. 30.06.2016 to all PwD employees who fulfill the eligibility condition as laid down in the DoPT O.M. dated 17.5.2022 (copy enclosed). The Ministries/ Departments are required to create supernumerary posts for extending the benefit of reservation in promotion to PwD employees on notional basis and to send such proposal to DoPT to enable this Department to seek concurrence of Department of Expenditure. However, proposal has not been received from any Ministry/Department so far.

2. In this regard, it is reiterated that as per the above mentioned O.M. dated 28.12.2023, it is provided, "extending the benefit of reservation in promotion to the PwD employees on notional basis between 30.6.2016 and actual assumption of the charge of the post may affect the inter-se-seniority of the officials in various grades. Due to this, there may be cases in which some officials may have to be placed in a select-list/seniority list, subsequent to the year of their existing/present seniority list/select list. This may have a chain effect as it may result in revision in seniority lists in subsequent years in many cases which may cause administrative inconvenience. In order to avoid such situation, supernumerary posts may be created to adjust the lien of such PwD employees with effect from the date on or after 30.6.2016, when they become eligible to get the benefit of reservation in promotion, till the availability of vacancy in which the promotion is to be made or till they vacate the post on their retirement, further promotion etc. whichever is earlier."

3. In view of the above, Ministries/ Departments, vide OM dated 28.12.2023, were requested fir the following :

(i) To undertake an exercise to ascertain the requirement of supernumerary posts required to be created in order to grant the benefit of reservation in promotion to PwD employees, who would have become eligible for such benefit during the period from 30.6.2016 to 16.5.2022 but could not be given such benefit due to absence of instructions in the matter. The Ministries/ Departments were requested to submit . the proposal for creation of supernumerary posts to DoPT for sending the same to Department of Expenditure for concurrence.

(ii) Ministries/ Department were informed and requested to send such proposal in respect of the entire Department/ Ministry and not to send the proposal in piecemeal.

(iii) It was also requested that a certificate to the effect that the proposal is . complete in all respects and the requirement of creation of supernumerary posts has been projected in respect of the entire Department may also be furnished along with the proposal.

(iv) They were also requested that each proposal shall have the concurrence of the Liaison Officer for PwDs of the Department/Ministry concerned and shall be forwarded with the approval of the Secretary of the Administrative Department / Ministry.

4. As already mentioned in para 1 above, the above instructions have been issued in pursuance of the Hon'ble Supreme Court directions. Hence, all Ministries/ Departments were required to take necessary action to ensure that the benefit of reservation in promotion is extended to the PwD employees from 30.6.2016 onwards as per their eligibility. However, proposal from Ministries/ Departments are awaited. Ministries/Departments are requested to undertake the exercise regarding ascertaining the requirement of creation of supernumerary posts for the purpose of granting the notional benefit of reservation in promotion to PwD employees during the notional benefit of reservation in promotion to pWD employees during the period from 30.6.2016 to 16.5.2022 in terms of DoPT O.M. dated 17.5.2022 and O.M. dated 28.12.2023 and submit the proposal to DoPT in the prescribed proforma (Annexure-I) at the earliest and latest by 31.12.2024. In case there is no such proposal from any Ministry/Department, NIL. Information may be provided/furnished.

5. This issue with the approval of Joint Secretary (AT&A). ❐

No. A-27018/02/2022-Estt.(AL) Government of India Ministry of Personnel, PG & Pensions Department of Personnel & Training Dated : 2nd Oct. 2022

Sub.: Consolidated instructions on Risk Allowance to Central Government employees.

Consequent upon the decision taken by the Government on the recommendations made by the 7th Central Pay Commission on the subject of Risk Allowance and with the approval of D/o Expenditure, the rates of Risk Allowance were revised vide this Department O.M. No.- A-27018/01/2017-Estt.(AL) dated 03.11.2020. Risk Allowance with revised rates has been payable from the date of issue of above mentioned OM with all other conditions envisaged in the

OM No. 21012/4/88-Allowances dated 22.08.1988. However, for the purpose of ease of access, it has been decided to issue consolidated instructions on the subject of Risk Allowance to Central Government employees.

2. Risk Allowance is presently given to Central Government employees engaged in hazardous duties or whose work will have a deleterious effect on health over a period of time.

i. For determining the categories of staff exposed to risk in employment the following criteria may be adopted:-

- those engaged in duties involving greater hazards or whose health is liable to be adversely affected progressively over a long period of time because of the particular avocation, and
- Sweepers/Safaiwalas engaged in cleaning of underground drains, sewer lines, those working in trenching grounds and Infectious Diseases Hospitals.

ii. The existing categories of Government servants who are in receipt of Risk Allowances may continue to get the same, at revised rates (w.e.f. 03.11.2020) as under:-

Sl. No.	Categories of employees	Revised Rates in Rupees per Month
1.	Unskilled workers	90
2.	Semi-skilled workers	135
3.	Skilled workers	180
4.	Supervisors	225
5.	Non-gazetted officer engaged in Nitro Glycerine preparation	405
6.	Gazetted officer engaged in Nitro Glycerine preparation	675
7.	Danger Building Officers	900

iii. Where a category of Government servants in a Department is in receipt of Risk Allowance, similar categories of Government servants in other Ministries/Departments shall also be considered for grant of Risk Allowance under similar conditions, e.g. Safaiwalas/Sanitary Cleaners working in underground drains, sewer lines, infectious diseases hospitals etc.

iv. The Risk Allowance will not be treated as "Pay" for any purp,ose.

3. Proposal for inclusion of any new category fulfilling the criteria as indicated above may be processed by the concerned Ministries in consultation with their Associate Finance and the Department of Personnel & Training. Further in identifying such categories, Staff Side of the Departmental Council (JCM) may also be consulted.

4. It has also been decided that Ministries/ Departments may work out suitable welfare schemes for periodical medical check-up of the staff exposed to risk in their job to ensure their good health. ❐

F.No. 31011/3/2022 - PP. A-IV Government of India Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions Department of Personnel & Training (Pers. Policy Division) Dated : 14th January. 2025

Sub.: Admissibility to travel by Tejas Express, Vande Bharat Express & Humsafar Express trains under Leave Travel Concession (LTC)-reg.

The undersigned is directed to refer to this Department's O.M. No. 31011/8/2017-Estt.A-IV dated 19.09.2017 regarding admissibility to travel by premium/ specific trains under CCS(LTC) Rules, 1988.

2. This department has been receiving a number of references from different offices /individuals about the admissibility of various premium trains like Tejas Express, Vande Bharat Express & Humsafar Express trains under Leave Travel Concession.

3. The matter has been examined by this Department in consultation with Department of Expenditure and it has been decided that apart from existing Rajdhani, Shatabdi and Duronto trains, travel by Tejas Express, Vande Bharat Express & Humsafar Express trains under LTC as per the entitlement of the Government employees, has now been allowed, as under:-

Pay Level in Pay Matrix (as per 7th Central Pay Commission) of the Central Government employees	Travel Entitlement for LTC in Premium Trains (i.e. Rajdhani, Shatabdi, Duronto, Vande Bharat Express Trains)	
	Shatabdi, or Similar Type Trains	Rajdhani Type or Similar Type Trains
Level 12 and above	Executive Class	AC 1st Class
Level 6 to 11	Chair Car	AC 2nd Class
Level 5 and below	Chair Car	AC 3rd Class

4. The other terms and conditions of O.M. No. 31011/8/2017-Estt.A-IV dated 19.09.2017 shall remain the same.

5. This issues with the approval of Competent Authority.

❐

DDP I. D. no. 8(94)2021-D(Coord)/DDP) Government of India Ministry of Defence Department of Defence Production Directorate of Ordnance (C&S) Dated : 28th November, 2024

Sub.: Reservation in promotion with benchmark disabilities - regarding

In the said context, the required number of supernumerary posts for promotion in r/o Persons with Benchmark Disability (PwBD) as sought in revised format (enclosed with ibid ID) is as follows:

Name of the post in which supernumerary post is proposed to be created	No of such supernumerary posts is proposed to be created							Pay Level	Financial implication involved	Remarks (if any)
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
AWM	2	0	2	0	2	1	2	10	NIL	As regards financial implication, the same is NIL as the promotion to the PwD employee will be on notional basis and no arrear will be admissible to them in accordance with extant DoP&T instructions.
JWM (SG)	3	4	2	9	3	1	6	8		
Sr. PS	0	0	0	0	0	0	1	8		
PGT	0	0	0	0	0	0	1	8		
JWM	35	8	14	3	27	7	6	7		
PS	2	0	0	0	0	0	0	7		
Chargeman	5	11	7	6	15	5	10	6		
Assistant	1	1	2	0	0	0	0	6		
IEs(MCM)	10	7	9	13	11	11	14	6		
IEs(HS-I)	8	9	7	14	19	26	19	5		
Supervisor	0	1	0	1	0	2	1	4		
IEs(HS-II)	8	12	14	13	12	13	5	4		
UDC	0	0	0	0	0	0	2	4		
LDC	0	0	1	0	0	0	0	2		
TOTAL	74	53	58	59	89	66	67			
GRAND TOTAL	466									

This issues with the approval of competent authority. ❐

UNIFIED PENSION SCHEME NOTIFICATION

F. No. FX-1/3/2024-PR MINISTRY OF FINANCE (Department of Financial Services) Dated : 24th January, 2025

In partial modification of the Ministry of Finance (Department of Economic Affairs) Notification No. F. No. 5/7/2003-ECB&PR dated 22" December, 2003 and Ministry of Finance (Department of Financial Services) Notification No. F. No. 1/3/2016-PR dated 31* January, 2019, the Central Government has decided to introduce Unified Pension Scheme, as an option under the National Pension System for the employees of the Central Government who are covered under the National Pension System.

2. The Unified Pension Scheme shall be applicable to such Central Government employees who are covered under National Pension System and who choose this option under National Pension System. It will have the following features, namely: -

Eligibility under the Scheme :

1) Assured Payout shall be available only in the following cases, namely: -

(a) in case of an employee superannuating after qualifying service of ten years, from the date of

superannuation;

(b) in case of the Government retiring an employee under the provisions of FR 56 (j) (which is not a penalty under Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965) from the date of such retirement; and

(c) in case of voluntary retirement after a minimum qualifying service period of 25 years, from the date such employee would have superannuated, if the service period had continued to superannuation.

(ii) Assured Payout shall not be available in case of removal or dismissal from service or resignation of the employee. In such cases, the Unified Pension Scheme option shall not apply.

Benefits under the Scheme

(iii) Subject to other conditions stated in this notification, Assured Payout under the scheme shall be as follows, namely: -

(a) the rate of full assured payout will be @50% of twelve monthly average basic pay, immediately prior to superannuation. Full assured payout is payable after a minimum 25 years of qualifying service;

(b) in case of lesser qualifying service period, proportionate payout would be admissible;

(c) a minimum guaranteed payout of Rs. 10,000 per month shall be assured in case superannuation is after ten years or more of qualifying service; and

(d) in cases of voluntary retirement after a minimum 25 years of qualifying service, assured payout will commence from the date on which the employee would have superannuated, if he had continued in service.

(iv) In case of death of the payout holder after superannuation, family payout @60% of the payout admissible to the payout holder, immediately before his demise, will be assured to the legally wedded spouse (spouse legally wedded as on the date of superannuation or on the date of voluntary retirement or retirement under FR 56(j), as may be applicable).

(v) Dearness Relief will be available on the assured

payout and family payout, as the case may be. The Dearness Relief will be worked out in the same manner as Dearness Allowance applicable to serving employees. Dearness Relief will be payable only when payout commences.

(vi) A lump sum payment will be allowed on superannuation @10% of monthly emoluments (basic pay + Dearness Allowance) for every completed six months of qualifying service. This lump sum payment will not affect the quantum of assured payout.

(vii) The corpus under the Unified Pension Scheme option will comprise of two funds, namely:-

(a) An individual corpus with employee contribution and matching Central Government contribution; and

(b) A pool corpus with additional Central Government contribution.

(viii) The contribution of employees will be 10% of (basic pay + Dearness Allowance). The matching Central Government contribution will also be 10% of (basic pay + Dearness Allowance). Both will be credited to each employee's individual corpus.

(ix) Central Government shall provide an additional contribution of an estimated 8.5% of (basic pay + Dearness Allowance) of all employees who have chosen the Unified Pension Scheme option, to the pool corpus on an aggregate basis. The additional contribution is for supporting assured payouts under the Unified Pension Scheme option.

(x) The employee can exercise investment choices for the individual corpus alone. Such investment choices shall be regulated by the Pension Fund Regulatory and Development Authority. A 'default pattern' of investment may be defined by Pension Fund Regulatory and Development Authority from time to time. If an employee does not exercise an investment choice on individual corpus, the 'default pattern' of investment will apply.

(xi) The investment decisions for the pool corpus built through the additional Central Government contribution will solely rest with Central Government.

(xii) In respect of employees who have retired before the date of operation of Unified Pension Scheme and who opt for the Unified Pension Scheme option, Pension Fund Regulatory and Development Authority will determine the mechanism for making available the top-up amount.

Explanation: For the purpose of this notification basic pay includes non-practicing allowance granted to medical officer in lieu of private practice.

3. The existing Central Government Employees under National Pension System, on the effective date of operationalisation of the Unified Pension Scheme option, as well as the future employees of Central Government can choose to either take the Unified Pension Scheme option under the National Pension System or continue with the National Pension System without the Unified Pension Scheme option. In case an employee chooses the Unified Pension Scheme option, all its stipulations and conditions shall be deemed to have been opted for and such option once exercised, shall be final.

4. Once an employee covered under National Pension System, who is in service on the effective date of operationalisation of the Unified Pension Scheme option, exercises the Unified Pension Scheme option, the outstanding National Pension System corpus in the employees Permanent Retirement Account Number shall be transferred to the employee's individual corpus under the Unified Pension Scheme.

5. For each employee covered under National Pension System who has exercised the Unified Pension Scheme option, a 'benchmark corpus' value shall be computed, in such manner as may be determined by the Pension Fund Regulatory and Development Authority, with the following assumptions, namely: -

(i) regular receipt of applicable contributions for both the employees and the employer for each month of qualifying service;

(ii) in case of missing contributions, an appropriate value, to be determined by the Pension Fund Regulatory and Development Authority, shall be assigned; and

(iii) investment of such contributions is made as per the 'default pattern' of investment, as defined by the Pension Fund Regulatory and Development Authority.

6. The value or units in the individual corpus with investment choices of the employee shall be informed to such employee on a periodic basis. Alongside, the value or units of the benchmark corpus corresponding to theemployee, computed as per para 5 above will also be informed to the employee.

7. At superannuation or retirement, the qualifying service of the employee under the Unified Pension Scheme option, will be determined by the Head of Office, where he is employed.

8. At superannuation or retirement, the employee under Unified Pension Scheme shall authorise transfer of the value or units in the individual corpus to the pool corpus,

equivalent to the value or units of the benchmark corpus for authorisation of Assured Payout. In case the value or units of individual corpus is less than value or units of the benchmark corpus, the employee will have an option to arrange for additional contribution to meet this gap. In case the value or units of individual corpus is more than the value or units of the benchmark corpus, the employee shall authorise transfer of value or units equivalent to the benchmark corpus and the balance amount in the individual corpus will be credited to the employee.

9. In case the values or units transferred by the employee from the individual corpus to the pool corpus, is less than the value or units of the benchmark corpus, payout proportionate to the assured payout shall be authorised.

10. The Unified Pension Scheme, being a 'fund-based' pension system, relies on the regular and timely accumulation and investment of applicable contributions (from both the employee and the employer) for Assured Payout to the employees.

11. For the sake of clarity, it is made clear that any employee who has exercised the Unified Pension Scheme option under National Pension System under this notification, shall not be entitled for and cannot claim, any other policy concession, policy change, financial benefit, any parity with subsequent retirees etc. later including post- retirement.

12. The provisions of Unified Pension Scheme will also be applicable, mutatis mutandis to past retirees of National Pension System, who have superannuated before the date of operationalising of Unified Pension Scheme. Such superannuated employees will be paid arrears for the past period along with interest as per Public Provident Fund rates. The monthly top-up amount for such superannuated employees, to be determined by the Pension Fund Regulatory and Development Authority, will be paid after adjusting the withdrawals made by, and annuities paid to, them.

13. The provisions regarding assured payout under the Unified Pension Scheme option for employees facing disciplinary proceedings at the time of superannuation or where disciplinary proceedings are contemplated post- retirement, shall be separately notified.

14. Illustrative examples as to working of payouts of Unified Pension Scheme under different scenarios are given in the Annexure.

15. Pension Fund Regulatory and Development Authority may issue regulations for operationalising Unified Pension Scheme.

16. The effective date for operationalisation of the Unified Pension Scheme shall be 1* April, 2025.

ANNEXURE REFERRED TO IN PARAGRAPH 14 OF THE MINISTRY OF FINANCE (DEPARTMENT OF FINANCIAL SERVICES) NOTIFICATION F. NO. FX-1/3/2024-PR DATED- THE 24" JANUARY, 2025

A. Illustrative Examples of Admissible Monthly Assured Payout

A set of different scenarios have been considered with the following set of assumptions, namely:-

(i) The 12 monthly average basic pay before superannuation of an employee is Rs 45,000 (denoted as P).

(ii) The employee has a qualifying service (based on the number of months of contribution) of 25 years (300 months) or more (denoted as Q).

(iii) All contributions of the employee have been credited regularly and there are no missing credits.

(iv) The employee has opted for 'default pattern' of investment.

(v) The employee did not make any partial withdrawals

Scenario 1: The employee fulfils all conditions (i) to (v).

- The value of the individual corpus of the employee at retirement is Rs 50,00,000 (10,000 units) (denoted as IC).
- The value of the benchmark corpus in this case should also be Rs 50,00,000 (10,000 units) (denoted as BC).
- The assured payout of the employee will be

  = (P/2) x (Q/300) x (IC/BC) with the condition that;

(i) if Q exceeds 300, it will be taken as 300.

(ii) if (P/2) XQ/300 is less than 10,000, it will be taken as 10,000.

= (45,000/2) x (300/300) x (50,00,000/50,00,000) =

Rs 22,500 plus applicable Dearness Relief (DR)

NOTE:- In this case assured payout equals full assured payout

Scenario 2: The employee fulfils the conditions (i) and (iii) to (v). The employee has a qualifying service (based on the number of months of contribution) of 15 years (180 months).

• The value of the individual corpus of the employee at retirement is Rs 30,00,000 (8,000 units) (denoted as IC).

• The value of the benchmark corpus will be Rs 30,00,000 (8,000 units) (denoted as BC).

• The assured payout of the employee will be

= (P/2) x (Q/300) x (IC/BC) with the condition that

(i) if Q exceeds 300, it will be taken as 300.

(ii) if (P/2) XQ/300 is less than 10,000, it will be taken as 10,000.

= (45,000/2) x (120/300) x (25,00,000/25,00,000) =

Rs 9,000

which will be raised to the minimum assured payout of Rs.10,000 plus applicable Dearness Relief (DR). as the full value of the bench mark corpus has been deposited from the individual corpus to the pool corpus.

Scenario 3(a): The employee fulfils the conditions (i) and (iii) to (v). The employee made partial withdrawals. The employee has a qualifying service (based on the number of months of contribution) of 10 years (120 months).

• The value of the individual corpus of the employee at retirement is Rs 22,00,000 (8,800 units) (denoted as IC).

• The value of the benchmark corpus will be Rs 25,00,000 (10,000 units) (denoted as BC).

• The assured payout of the employee will be

= (P/2) x (Q/300) x (IC/BC) with the condition that

(i) if Q exceeds 300, it will be taken as 300.

(ii) if (P/2) XQ/300 is less than 10,000, it will be taken as 10,000.

= (45,000/2) x (120/300) x (22,00,000/25,00,000) =

Rs 8,800

In this case payoout will be Rs. 8800 plus applicable Dearness Relief (DR). as full corpus has not been deposited from the individual corpus to the pool corpus.

Scenario 4: The employee fulfils the conditions (i), (ii), (iv) and (v). All contribution of the employee have not been credited regularly and these are some missing credits which has been made good/ arranged to be good by the employee.

• The value of the individual corpus of the employee at retirement is Rs 45,00,000 (9,000 units) (denoted as IC).

• The value of the benchmark corpus is Rs 50,00,000 (10,000 units) (denoted as BC). The benchmark corpus has been worked out considering an average contribution for the missing credits.

• The assured payout of the employee will be

= (P/2) x (Q/300) x (IC/BC) with the condition that

(i) if Q exceeds 300, it will be taken as 300.

(ii) if (P/2) XQ/300 is less than 10,000, it will be taken as 10,000.

= (45,000/2) x (300/300) x (45,00,000/50,00,000) =

Rs 20,250 plus applicable Dearness Relief (DR)

Scenario 5 : The employee fulfils the conditions (i) to (iv). The employee made partial withdrawals. the value of vis-a-vis the benchmark corpus, has not been recouped by the employee before retirement.

• The value of the individual corpus of the employee at retirement is Rs 40,00,000 (8,800 units) (denoted as IC).

• The value of the benchmark corpus will be Rs 50,00,000 (10,000 units) (denoted as BC). The benchmark corpus will be worked out considering no partial withdrawals.

• The assured payout of the employee will be

= (P/2) x (Q/300) x (IC/BC) with the condition that

(i) if Q exceeds 300, it will be taken as 300.

(ii) if (P/2) XQ/300 is less than 10,000, it will be taken as 10,000.

= (45,000/2) x (300/300) x (40,00,000/50,00,000) =

Rs 18,000 plus applicable Dearness Relief (DR)

Scenario 6: The employee fulfils the conditions (i), (ii),(iii) and (v). The employee employee opted for investment choices in the individual corpus and the value of the individual corpus is higher than benchmark corpus.

• The value of the individual corpus of the employee at retirement is Rs 55,00,000 (11,000 units) (denoted as IC).

• The value of the benchmark corpus is Rs 50,00,000 (10,000 units) (denoted as BC). The

benchmark corpus has been worked out based on 'default pattern' of investment.

- The assured payout of the employee will be

  = (P/2) x (Q/300) x (IC/BC) with the condition that

(i) if Q exceeds 300, it will be taken as 300.

(ii) if (P/2) XQ/300 is less than 10,000, it will be taken as 10,000.

= (45,000/2) x (300/300) x (50,00,000/50,00,000) =

Rs 22,500 plus applicable Dearness Relief (DR)

In this case, the employee will get a credit of the excess value of individual corpus vis-a-vis benchmark corpus (i.e. Rs. 5,00,000) in this designated bank account at retirement.

Scenario 7 : The employee fulfils the conditions (i) , (ii), (iii) and (v). TThe employee employee opted for investment choices in the individual corpus and the value of the individual corpus is higher than benchmark corpus.

(a) If the employee does not recoup the individual corpus:

- The value of the individual corpus of the employee at retirement is Rs 45,00,000 (9,000 units) (denoted as IC). as the employee did not recoup the value of the individual corpus vis-a-vis the benchmark corpus owing to the investment choices exercised by the employee.

- The value of the benchmark corpus is Rs 50,00,000 (10,000 units) (denoted as BC). The benchmark corpus has been worked out based on 'default pattern' of investment.

- The assured payout of the employee will be

  = (P/2) x (Q/300) x (IC/BC) with the condition that

(i) if Q exceeds 300, it will be taken as 300.

(ii) if (P/2) XQ/300 is less than 10,000, it will be taken as 10,000.

= (45,000/2) x (300/300) x (45,00,000/50,00,000) =

Rs 20,250 plus applicable Dearness Relief (DR)

(b) If the employee partially recoups the individual corpus:

- The value of the individual corpus of the employee at retirement is Rs 45,00,000 (9,000 units) (denoted as IC). as the employee recouped partially the individual corpus by Rs. 2,50,000, so the corpus now stands at Rs. 47,50,000 (9,500 Units).

- The value of the benchmark corpus is Rs 50,00,000 (10,000 units) (denoted as BC). The benchmark corpus has been worked out based on 'default pattern' of investment.

- The assured payout of the employee will be

  = (P/2) x (Q/300) x (IC/BC) with the condition that

(i) if Q exceeds 300, it will be taken as 300.

(ii) if (P/2) XQ/300 is less than 10,000, it will be taken as 10,000.

= (45,000/2) x (300/300) x (47,50,000/50,00,000) =

Rs 21,375 plus applicable Dearness Relief (DR)

B. Illustrative examples of Lump Sum Payment on superannuation or VR after 25 years of qualifying service and retirement under FR 56(j)

The Basic Pay at the time of retirement and Dearness Allowance have been assumed as under:

Basic pay as on the date of superannuation or VR or retirement under FR 56(j)	**Rs. 45,000**
Dearness Allowance thereon @ 53%	**Rs. 23,850**
Total emoluments	**Rs. 68,850**

Lump sum amount = ($\frac{1}{10}$ X 68,850) X L = 6,885 X L

Where **L** =number of six-monthly completed years of service based on the number of months for contribution to individual's pension corpus

Amount of Lump Sum, depending upon the length of qualifying service:

1/10 of emoluments (Rs)	Length of qualifying service (number of months of contribution) L	Number of completed 6 months	Amount of Lump sum (Rs)
6,885	10 years (120 months)	20	1,37,700
	15 years(180 months)	30	2,06,550
	20 years (240 months)	40	2,75,400
	25 years (300 months)	50	3,44,250
	30 years (360 months)	60	4,13,100
	35 years (420 months)	70	4,81,950

NOTE: No lump sum will be payable, if the service length is less than 10 years (less than 120 months of contribution), as Unified Pension Scheme is not applicable in such a case.

हमारा संघर्ष पुरानी पेंशन स्कीम
को लागू कराना है।
तब तक संघर्ष जारी रहेगा

देश भर के रक्षा संस्थानों में 5 सूत्रीय मांगो को लेकर आन्दोलन करते भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ के कार्यकर्ता

RNI No. MAHBIL/2002/8760 Publication Date : 30 January 2025
Postal Regd. No. Misc-II/C.P.M//007/K.PH.O./2020 dt 29-12-2020 (for 2021-23)• Posted on Dt. 26,27th Monthly
MONTHLY NEWS PAPER

Bharatiya Pratiraksha Mazdoor Sangh

(An Industrial Unit of BMS)

Recognized by Ministry of Defence, Govt. of India.

PRATIRAKSHA BHARATI

SPECIAL BULLETIN

Date:-24|Jan|2025 Sr.No- 02/2025

भावपूर्ण श्रद्धांजलि

Lost our brothers in the massive blast at Ordnance Factory Bhandara.

In a tragic and massive explosion took placed today in Ordnance Factory Bhandara, we lost our fellow brothers. The explosion took place around 10:00 am (approx) that gripped lives of 8 employees and left more than 5 seriously injured. This tragedy has shocked the entire nation.

BPMS hereby express our grief , sympathy and stands with family members on this grave situation. We pray before the almighty for speedy recovery of the injured ,bestow enough strength on the family members to bear this irreparable loss.

Shahid kamgar Amar Rahe

2A, Navin Market, Kanpur-208001. Email: info@bpms.org.in /gensecbpms@yahoo.co.in

कृपया अपनी प्रतिक्रियाएँ हमें इस पते पर भेजिये।

If undelivered please return to :

"Pratiraksha Bharti"
C/o. Bharatiya Pratiraksha Mazdoor Sangh
2, Naveen Market, Kanpur - 208 001
Mob. : 9450153677, Tel./Fax : 0512-2332222
Website : www.bpms.org.in
E-mail : gensecbpms@yahoo.co.in, cecbpms@yahoo.in

बुक पोस्ट

Publisher and Owner : Bhartiya Pratiraksha Mazdoor Sangh, 2 Naveen Market, Kanpur-208001
Printed at Chhaya Press 8/208, Arya Nagar, Kanpur-208002 • Mob. : 9839223650